भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 801
14 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल्याण योजनाएं

801. डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजनाएं ला रहा है; और
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क)और (ख): सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों का निर्माण करके मध्य प्रदेश और इसके आदिवासी क्षेत्रों सहित, देश भर में जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करके, विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ, सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है:

- 2,516 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना।
- सहकारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना (सी.आई.एस.आई.ए.सी.) के तहत सहकारी समितियों को सब्सिडी / अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 341.67 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 47.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंचायत स्तर पर पैक्स को बहुउद्देश्यीय जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के लिए आदर्श उपनियम तैयार करना।
- सभी हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण करना।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सी.जी.टी.एम.एस.ई.)के तहत पात्र शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (मेम्बर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन्स) के रूप में शामिल करना।
- जेमपोर्टल पर "खरीदारों" के रूप में सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग ।

तत्कालीन सी.एस.आई.एस.ए.सी. योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विशिष्ट वरीयता वाली सहकारी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) ने143 आदिवासी सहकारी समितियों के लिए 68.64 करोड़ रुपये संवितरित किया है।

*****